(c) and (d) The pay scale of Assistants in the Central Secretariat Service was revised to set right an anomaly Since no such anomaly exists in the pay scale of UDCs, the question of revising the pay scale of UDCs does not arise

OFFICE MEMORANDUM

No 2/1/90-CS IV New Delhi, dated the 31st July, 1990

Subject Revision of scale of pay of Assistant Grade of Central Secretariat Service and Grade 'C' Stenographers of Central Secretariat Stenographers Service

The undersigned is directed to say that the question regarding revision of scale of pay for the post of Assistants in the Central Secretariat etc, has been under consideration of the Government in terms of order dated 23rd May, 1989 in OA No 1538/87 by the Central Administrative Tribunal Principal Bench, New Delhi for some time past The President is now pleased to prescribe the revised scale of Rs 1640-60-2600-EB-75-2900 for the pre-revised scale of Rs 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 for duty posts included in the Assistant Grade of Central Secretariat Service and Grade C' Stenographers of Central Secretariat Stenographers Service with effect from 1-1-1986 The same revised pay scale will also be applicable to Assistants and Stenographers in other Organisations like Ministry of External Affairs which are not participating in the Central Secretariat Service and Central Secretariat Stenographers Service but where the posts are in comparable grades with same classification and pay scales and the method of recruitment through open Competitive Examination is also the same

2 Pay of the Assistants and Grade 'C' Stenographers in position as on 1-1-1986 shall be fixed in terms of Central Civil Service (Revised Pay) Rules, 1986. The employees concerned shall be given option to opt for the revised scale of pay from 1-1-1986 or subsequent date in terms of Rule 5 *ibid*, read with Ministry of Finance O M No 7(52)-E III/86 dated 22-12-1986 and 27-5-1988 in the form appended to Second Schedule of the rule *ibid* This option should be exercised within three months of the date of issue of this O.M. The option once exercised shall be final

3 Formal amendment to CSS(RP) Rulels, 1986 will be issued in due course

4 This issues with the concurrence of Ministry of Finance (Department of Expenditure) vide their U O No 7(43)-IC/89 dated 30-7-1990

Minister's Comments about Additional Soliciter General

907 SHRI CHIMANBHAI MEHTA Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state

(a) whether it is a fact that he had made certain appreciative as also some critical remarks regarding Additional Solicitor General, Shri Tulsi and CBI Deputy Director, Shri Madhavan in the pending appeal in Delhi High Court with reference to Bofors scandal,

(b) whether it is also a fact that what was upheld by the Federal Court of Switzerland was found vague by the Additional Solicitor General,

(c) what are the concrete and vague allegations made in the CBI's appeal;

(d) whether it is also a fact that the Attorney General was given guidance and instructions in this particular case; and

(e) what were the reasons for opposing the FIR by CBI in this case?

THE MINISTER OF COMMERCE WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI SUBRAMANIAN SWAMY): (a) The Minister of Law and Justice had observed that the CBI Joint Directors intervention in the Delhi High Court was uncalled for.

(b) and (c) Since the matter is sub-judice no detail can be furnished

(d) No, Sir.

(e) The Government did not oppose the FIR by CBI.

बाढ़ और अकाल के लिए राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

908. **डा० अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विभिन्न राज्यों को बाढ़ और अकाल के लिए अब तक राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता दी गई हैं तथा इस प्रकार की सहायता का मानदंड क्या है, और

(ख) क्या बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के मामले में बैंक भी कोई सहयता या ऋण प्रदान करता है; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1990-95 के लिए प्राकृतिक आपदा राहत व्यय का वित्त पोषण नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट की सिफारिशों द्वारा शासित होना है। तदनुसार राहत व्यय को पूरा करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष स्थापित किया जाना है जिसमें सभी राज्यों के लिए प्रतिवर्ष 804 करोड़ रु० की राशि होगी। इस कोष में केन्द्र 75% या 603 करोड रु० प्रतिवर्ष का अंशदान करेगा शेष 25% का अंशदान राज्य सरकारो को करना हैं। सरकार ने इन सिफ़ारिशो को स्वीकार कर लिया है। चालू वर्ष में अब तक केन्द्र के अंशदान के रूप में राज्य सरकारों को कुल 410 09 करोड़ रु० की राशि दी गई है। उसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिए)**

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर० बी० आई०) ने हर बार भारतीय रिजर्व बैंक से अनुदेशो की प्रतीक्षा किए बिना बाढ़ सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सहायता देने के लिए 1984 में बैंकों को स्थाई मार्गनिर्देशन जारी कर दिये थे। इन मार्गनिर्देशनों में अन्य बातों के साथ-साथ (1) अल्पावधि उत्पादन ऋण को मध्यावधि ऋण में बदलना (2) ऋण की किस्तों की वर्तमान शर्तों का पुनः निर्धारण/मुलतवी करना और (3) अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार फसल/निवेश ऋण आदि की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। किसी प्रभावित व्यक्ति को उसके व्यापार चलाने/कार्यकिलाप करने के लिए बैंक द्वारा दिए गये नये अग्रिमों या अन्य किसी रियायत के रूप में दी गई सहायता उस क्षेत्र मे उनके अग्रिम का भाग बन जाता हैं और इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए अलग से रिपोर्ट करने की पद्धति निर्धारित नही की है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	नौवें वित्त आयोग द्वारा आबंटित कुल राशि	आपदा राहत कोष में केन्द्र का अंशदान	31-12-90 तक दी गई राशि
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश . .	86.00	64.50	64.5000 +61.1564*

* इसमें चक्रवात राहत व्यय को पूरा करने के लिए 1990-91 मे अग्रिम रूप से दिया गया केन्द्र का अशदान भी सम्मिलित है। इसको 1991-92 से 1994-95 तक के दौरान राज्य के कोष में केन्द्र के अंशदान के रूप में चार बराबर-बराबर किश्तों में समायोजित किया जाएगा।